RAJYA SABHA

Wednesday, the 10th May, 2000/20 *Vaisakha,* 1922 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock, *MR. CHAIRMAN in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Filling up the Post of CMD and Directors

*621. SHRI BHAGATRAM MANHAR: Will the Ministerof POWER be pleased to state:

(a) whether it is fact that post of CMD and Directors in some Public Sector Undertakings under the Ministry of Power are lying vacant for more than one year;

(b) whether it is also a fact that some stop-gap arrangements have been made to fill these vacancies;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) what steps are being taken to fill these vacancies through proper selection?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI JAYAWANTI MEHTA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the,House.

STATEMENT

(a) to (d) Out of the posts of CMDs/functional Directors only the post of Director (Projects), National Hydro-Electric Power Corporation Limited (NHPC), has been lying vacant since 06.08.1998 consequent upon the appointment of the then incumbent of the post as CMD of the same Corporation. No other post of CMD or Functional Director is vacant in any of the PSUs under Ministry of Power at present.

The CMD, NHPC, is also looking after the work of Director (Projects), NHPC in addition to his own duties.

The selection process for the Board level posts in the Central PSUs had to be kept on hold since August' 1998, as the Government was considering the upper age limit criterion in the context of enhancement of the age of superannuation from 58 to 60 years. In February' 1999, it was decided to raise

3230 RSS/2000—1

the upper age limit for consideration to a Board level position from 56 to 58 years. Fresh recruitment action was initiated thereafter and a panel of candidates was recommended by the Public Enterprises Selection Board (PESB) on 17.11.1999. The candidates recommended by the PESB require clearance from vigilance angle before the case for appointment is processed for approval of the competent authority. The clearance from vigilance angle has not been received so far and, therefore, the case could not be processed further.

SHRI BHAGATRAM MANHAR: Sir, in the NTPC, the CMD is retiring next month and the selection of his successor has already begun through the PSEB. The Power Trading Corporation was formed last year and is without a regular CMD. The Ministry has picked up the Director (Projects) from the Power Grid Corporation and given additional charge as CMD of the Power Trading Corporation. The selection process for regular appointment of the Power Trading Corporation has not begun as the Director (Projects) is not eligible for this post as he is retiring in the next year. Sir, I would like to know why a regular CMD has not been appointed in the Power Trading Corporation and when this post will be fdled up. I would also like to know the reasons for not appointing some Joint Secretary till such time new CMD is selected and why there is a preferential treatment in this case.

श्रीमती जयवंती मेहता : माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसके बारे में मैं यही बताना चाहती हूं कि यह सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के माद्यम से सरकार द्वारा अनुरोध किया जाता है लेकिन आप जो पूछ रहे हैं, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि 19 अगस्त को सार्वजनिक उद्यम चायन बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा अनुरोध किय गया था कि उसके ऊपर कार्यवाही की जाए । इसके पश्चात तीन बार यह कहा गया- 17 सितम्बर को कहा गया, 22 सितम्बर को कहा गया और 5 नवम्बर को कहा गया कि उसके बारे में आप उचित कार्यवाही करें इसलिए वहां से जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी, उसके बारे में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जाएगा ।

श्री भगतराम मनहर: सभापति महोदय, मेरे सवाल का जवाब मंत्री महोदया ने नहीं दिया है । जब यह नियम में है कि ज्वाइंट सैक्रेटरी इंचार्ज हो सकता है तो उसका अप्वाइंटमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? जब आपके रूल में है कि सी.एम.डी. की पोस्ट खाली हो जाए और योग्य व्यक्ति न मिले तो तब तक ज्वायन्ट सेक्रेटरी को यह पोस्ट मिलनी चाहिए थी तो फिर आप बाहर से क्यों ले रहे हैं?

श्रीमती जयवंती मेहता: क्षमा चाहती हूं, क्या आप डी.वी.सी. के बारे में बात कर रहे हैं?

श्री भगतराम मनहर: किसी भी ज्वाइंट सैक्रेटरी के बारे में है ।

श्रीमती जयवंती मेहताः आपने जो पूछा है, उसके लिए मैं यही बता सकती हूं कि भारत सरकार के शासकीय नियमों के अनुसार उसके संबंध में जो कार्यवाही करनी चाहिए, उसी प्रकार से कार्यवाही की जाती है। ज्वाइंट सैक्रेटरी को लाना,या पैनल में और किसी को लाना- वह आना चाहिए, उसके पश्चात सरकार उसके संबंध में निर्णय कर सकती है।

SHRI BHAGATRAM MANHAR: Sir, there are many Directors and CMDs in various PSUs under your Ministry facing *CVC* and CBI inquiries. The CVC is not giving clearance because some of them are facing grave charges. I would like to know how many such senior officers in various PSUs are facing grave charges and what steps are being taken to replace these senior officers with those of a clean record.

श्रीमती जयवंती मेहताः जहां तक हमारी जानकारी है, ऐसे किसी भी पद के लिए,जिनके नाम हैं, उनके ऊपर ऐसे कोई गंभीर आरोप नहीं लगे हुए हैं। विजिलेंस क्लीयरेंस होने के पश्चात ही उनकी अप्वाइंटमेंट की जाती है। मैं यही बताना चाहूंगी कि अभी तक सिर्फ एक ही पद जो रिक्त है- एन.एच.पी.सी. में डायरेक्टर (प्रोजैक्ट) का- उसी में विलम्ब हो रहा है उसके अतिरिक्त ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई पद रिक्त रहा हो और उसके लिए एक वर्ष से अधिक कार्यावधि चली गयी हो । ऐसा कोई पद रिक्त नहीं है ।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr Chairman. Sir. the hon. Minister has said in paragraph 2 of the reply that the CMD, NHPC, is also looking after the work of Director (Projects). NHPC, in addition to his own duties, for the last two years. I wonder if this post is really not required because if he can handle it for two years, probably, this post is superfluous. So, why should not we abolish this post? Or, perhaps, the present CMD does not want a second man to have a free hand of these activities. Similarly, can I have an assurance from the hon. Minister that any PSU under his Ministry will have a continuity? Will you appoint the chiefs, at least, one year in advance so that it is well known and take over is quite smooth?

श्रीमती जयवंती मेहताः माननीय सांसद ने जो सवाल पूछा है कि क्या सी.एम.डी. यह डायरेक्टर का रिक्त पद भरने के लिए इच्छुक नहीं है, तो इस बात में कोई तथ्य नहीं है । सी.एम.डी. को अधिक कार्यभार संभालना पड़ता है इसलिए उनकी तो यही इच्छ होगी कि यह पद तुरंत भर दिया जाए । लेकिन इसके लिए विलम्ब का एक कारण है कि उसी समय उद्यम विभाग में सेवानिवृति की आयु को 58 से बढ़ा कर 60 वर्ष करने के बारे में विचर चाल रहा था और उसी के कारण उस पद को भरने की निर्णय प्रक्रिया में बिलम्ब हुआ है । इसके लिए मैं यह कह सकती हूं कि 3 मार्च,1999 को पी.ई.एस.बी. को अर्द्धशासकीय पत्र के द्वारा यह सूचित किया गया था ।

कि इसके लिए आयु का काल बढाने की दृष्टि से विचार चल रहा है,इसलिए इसके पश्चात् ही यह रिक्त पद भरा जाएगा । अंत में मैं इस विषय पर यह कह सकती हूं कि 17 नवंबर,1999 को पुनर्निर्धारित किया गया और दो उम्मीदवारों के पैनल की सिफारिश की गई है और शीघ्र ही उस पद को भरा जाएगा ।

श्री शंकर राय चौधरी : माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य का सवाल था कि जो रिक्त पद हैं,उनमें ज्वाइंट सेक्रेटरी को क्यों न नियुक्त किया जाए । मैं माननीया मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि मुझे इसमें आई.ए.एस. लॉबी की अपने पंख फैलाने की कोई साज़िश लगती है । मैं उनसे आग्रह करना चाहूगा कि पोस्ट्स के लिए वे क्वालिफाईड टेक्नोक्रेट्स को लें ।

श्रीमती जयवंती मेहता: आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा ।

Power Plants by Foreign Power Companies in Gujarat

*622. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the details of foreign power companies permitted to set up power plants in Gujarat;

(b) the name of the companies which have set up such plants;

(c) whether there are some projects which have sought clearance pending with Government;

(d) the reasons for pendency; and

(e) the extent to which the power shortage will be reduced?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI JAYAWANTI MEHTA): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) M/s Siemens, Germany and M/s Power Gen. U.K. were permitted for equity participation in the Joint Venture Company formed by M/s Torrent Export Limited and Gujarat Power Corporation Limited (GPCL) in the name of Gujarat Torrent Energy Corporation Limited (now renamed as Gujarat Powergen Energy Corporation Limited) to set up the 655 MW dual fuel power plant at Paguthan in Bharuch Distict. Apart from this, the following private sector power projects in the State accorded techno-economic clearance by the Central Electricity Authority (CEA) also envisage foreign equity